

बैंक बोर्ड ब्यूरो

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21



निदेशक उद्घिकास कार्यक्रम



नियुक्तियां



विषय-वस्तु

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
I.	बैंक बोर्ड ब्यूरो	3
II.	सचिवालय के प्रमुख अधिकारी	4
III.	संक्षिप्त विवरण	5
IV.	नियुक्तियों हेतु संस्तुतियां	9
V.	नए प्रयास	13
VI.	डाटाबेस, आईटी सिस्टम और प्रशासनिक कार्य	20
VII.	प्रप्तियां और भुगतान लेखा	24

संक्षेपाक्षर-सूची

सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीएमडी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीडीपी	निदेशकों हेतु परिवर्धन कार्यक्रम
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीएमडी	उप प्रबंध निदेशक
एफआई	देखिए पी एस एफ आई
जीएम	महाप्रबंधक
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईआईएफसीएल	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी लिमिटेड
आईएफसीआई	आईएफसीआई लि.
आईपीपीबी	भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
एलडीपी	लीडरशिप विकास कार्यक्रम
एमडी	प्रबंध निदेशक
एमडी एंड सीईओ	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एमओएफ	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनईसी	गैर कार्यपालक अध्यक्ष
एनओडी	गैर-पदाधिकारी निदेशक
एनआरसी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
पीएसआईसी	सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
पीएसएफआई	सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं
आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
डब्ल्यूटीडी	पूर्णकालिक निदेशक

**बैंक बोर्ड ब्यूरो
गठन**

**सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय
संस्थान**

**सार्वजनिक क्षेत्र की
बीमा कम्पनियां**

**भानु प्रताप शर्मा
अध्यक्ष**

देबाशीष पांडा*

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
पदेन सदस्य

देबाशीष पांडा*

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
पदेन सदस्य

अली रजा रिजवी@

सचिव
लोक उद्यम विभाग
पदेन सदस्य

अली रजा रिजवी@

सचिव
लोक उद्यम विभाग
पदेन सदस्य

एम्. राजेश्वर राव#

उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
पदेन सदस्य

डा. एस. सी. खुंटिया&

अध्यक्ष
भाबीविविप्रा
पदेन सदस्य

वेदिका भंडारकर

पूर्व वाइस चेयरमैन और एमडी
क्रेडिट सुइसे
विशेषज्ञ सदस्य

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी*

पूर्व अध्यक्ष
सेबी और भारतीय जीवन बीमा निगम
विशेषज्ञ सदस्य

प्रदीप कुमार पांजा

पूर्व एमडी
भारतीय स्टेट बैंक
विशेषज्ञ सदस्य

एन. एम. गोवर्धन

पूर्व अध्यक्ष
भारतीय जीवन बीमा निगम
विशेषज्ञ सदस्य

प्रदीप पन्नालाल शाह

संस्थापक एमडी
क्रिसिल
विशेषज्ञ सदस्य

मैथ्यू वर्गीस*

पूर्व महाप्रबंधक
न्यू इंडिया एश्यूरेन्स कम्पनी लि.
विशेषज्ञ सदस्य

@ श्री शैलेश 31 मार्च 2021 तक पदेन सदस्य थे।

श्री महेश कुमार जैन 11 नवम्बर 2020 तक पदेन सदस्य थे।

& डॉ. एस. सी. खुंटिया का आईआरडीआई में कार्यकाल और परिणामस्वरूप मई 2021 तक पदेन सदस्य रहे।

* इन विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहा।

II. सचिवालय के प्रमुख अधिकारी

सचिव

डॉ. विजय सिंह शेखावत, महाप्रबंधक

सहायक महाप्रबंधक

ऋषभ गर्ग

प्रबंधक

प्रतीक जैन

सहायक प्रबंधक

देवांश रावत

आदित्य एम.

III. संक्षिप्त विवरण

इस वर्ष का आरंभ कोविड-19 महामारी की पहली लहर से हुआ और इसकी दूसरी लहर से समाप्त हुआ। इसकी वजह से इस वित्तीय वर्ष में काफी लम्बी अवधि के लिए सख्त लॉक डाउन लगा दिया गया। मुंबई में ब्यूरो का कार्यालय मार्च 2020 से ही बंद रहा और इसलिए घर पर रहते हुए ही कार्यालय का कार्य करने के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। यद्यपि नेमी प्रकार के कार्य कुछ कठिनाई से निपटाए जा रहे थे, लेकिन ऑन लाइन इन्टरएक्शन से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नई प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल की जरूरत थी। मुख्य विचार यही रहा कि सभी विद्यमान प्रक्रियाओं/दिशा निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करने के साथ-साथ भौतिक और सायबर सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरा किया जाए। इस बारे में समय पर की गई कार्रवाई के कारण ही बिना कोई समय नष्ट किए यह ब्यूरो अपने क्रियाकलापों को पुनः आरंभ करने में सक्षम रहा।

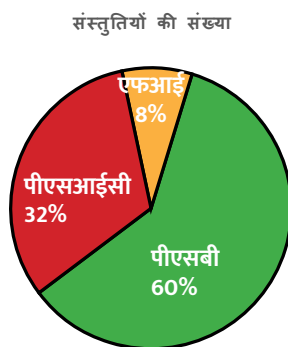
नियुक्तियों के लिए संस्तुतियां

वस्तुतः इस अवधि के दौरान इस ब्यूरो ने 21 दिन में रिकार्ड 19 बैठकों का आयोजन किया जिनमें व्यक्तियों के चयन के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के अभिशासन से संबद्ध कार्यसूची पर विचार-विमर्श किया गया।

ब्यूरो ने 173 अभ्यर्थियों के साथ वार्तालाप किया और इस प्रकार प्रत्येक रिक्त पद के लिए औसतन पाँच अभ्यर्थियों का अनुपात बरकरार रखा। इन सभी वार्तालापों में इस महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी), सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों (पीएसएफआई) में से किसी के भी बोर्ड स्तर के पदों हेतु आने वाले अभ्यर्थियों में से अधिकांश के लिए योग्यता आकलन और अन्य प्रकार की जांच को बनाए रखने के लिए व्यवस्था ब्यूरो द्वारा तैयार की गई। ब्यूरो ने अभ्यर्थियों का आकलन और आवेदन प्रस्तुत करने की पद्धतियों की समीक्षा की और अधिक दृढ़ तरीके अपनाने का निर्णय लिया। संशोधित प्रक्रिया में सतर्कता-प्रोफाइल प्रस्तुत करना निहित है, और सम्यक सामर्थ्य आकलन व्यवस्था के आधार पर आकलन पद्धतियों का संशोधन किया गया जो आकलन मानदंडों में ली जाने वाले विशेषताओं को साथ मिलाता है।

ब्यूरो द्वारा 38 व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए संस्तुतियां की गईं, जिनका विवरण

इस प्रकार है :-



वर्ग	एफआई	पीएसबी	पीएसआईसी	कुल
संस्तुतियों की संख्या	3	23	12	38

संस्तुतियां करने में औसतन 72 दिन का समय लगा। यह औसत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (76 दिन), सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (36 दिन) और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं (189 दिन) में पदों हेतु संस्तुतियों करने में लगने वाले समय का भारांकित औसत है। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के लिए संस्तुतियां करने में लगा औसत समय अधिक रहा क्योंकि सभी रिक्तियों के लिए पहले विज्ञापन देने पड़े, जबकि बीमा कंपनियों के मामले में वार्तालाप के लिए अभ्यर्थियों की सूची विचारार्थ दायरे और वरिष्ठता के आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रदान की गई। औसत समय को अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो आंतरिक अभ्यर्थियों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए यह 60 दिन रहा जबकि खुले विज्ञापनों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए यह 180 दिन रहा। विगत वर्ष में चयन और नियुक्ति में लगने वाला औसत समय कम था क्योंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भीतर ही निदेशकों के लेटरल मूवमेंट हुए जिसके लिए किसी प्रकार के विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं थी।

ब्यूरो को यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने इसकी सभी 38 संस्तुतियों (100 प्रतिशत) को स्वीकार कर लिया। नियुक्ति की प्रक्रिया का संचालन वित्तीय सेवाएं विभाग ने किया जिसमें ब्यूरो द्वारा संस्तुति करने की तारीख के बाद औसतन 4.4 माह का समय लगा। इसमें पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगने वाला समय और सक्षम प्राधिकारी से संस्तुतियों का अनुमोदन कराने में लगने वाला समय भी शामिल है। इन 38 नियुक्तियों में से चार को रिक्तियों की तारीख से पहले ही अधिसूचित कर दिया गया था।

कार्यनीति संबंधी बैठकें

ब्यूरो ने एक बैठक का पूरा समय अपने कार्यों के परिप्रेक्ष्य में दिए गए अधिदेश की समीक्षा के लिए दिया। अपने अधिदेश की समीक्षा करते हुए ब्यूरो ने अनुभव किया कि सभी अधिकारियों

के कार्यनिष्पादन हेतु एक डाटाबेस रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के डाटाबेस में उन अधिदेशित संस्थाओं के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का व्यक्तिगत विवरण, प्रशिक्षण और शिक्षा, पदोन्नतियों, पोस्टिंग, सतर्कता प्रोफाइल, आदि रखे जाए, जो आगामी वर्षों के दौरान बोर्ड स्तर की पोस्टिंग के लिए चयन की परिधि में आना संभावित हैं। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल आईटी केन्द्र के साथ मिलकर 'समेकन' नाम का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जो सन 2021 की दूसरी छमाही में लाइव हो जाने की संभावना है। एक बार लाइव हो जाने के बाद ब्यूरो के साथ-साथ सभी सहभागी संस्थान अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रोफाइल का सम्यक अवलोकन करने में सक्षम हो सकेंगे और मानव संसाधन के विभिन्न प्रकार के मेट्रिक्स यथा लिंगानुपातों, क्रेडिट, आईटी, आदि विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता, पोस्टिंग की औसत समयावधि, एक स्तर विशेष पर औसत आयु, संबंधी बेन्चमार्क रिपोर्ट अपने-अपने संस्थान और समस्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्राप्त कर सकेंगे।

दक्षता-वर्धन और सशक्तिकरण

बोर्डों की दक्षता के विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह जरूरत महसूस की गई कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों हेतु एक कार्यक्रम आरंभ किया जाए, ताकि उनके समस्त कार्यकाल के दौरान विशेषज्ञता के इनपुट और दक्षता संवर्धन की सहायता दी जा सके। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और भारतीय बैंक संघ के साथ परामर्श और सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का अवलोकन करने के बाद कार्यक्रम संचालन हेतु हावार्ड¹ बिजनेस पब्लिकेशन के सहकार्य में मैसर्स इगोन जेहन्डर इन्टरनेशनल प्रा. लि. का चयन किया गया। आशा है कि यह कार्यक्रम 2021-22 में आरंभ हो जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और एक्जिम बैंक से आने वाले सहभागियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों में दक्षता और व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य लेकर तैयार किए गए नेतृत्व विकास कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है। अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु द्वितीय बैच का प्रशिक्षण पूरी तरह से ऑनलाइन रहा जिसमें अन्य बातों के साथ आईआईएम बंगलोर के आभासी मंच पर एक इवेंट और लाइव प्रोजेक्ट भी शामिल किए गए थे। इस कार्यक्रम के तीसरे बैच का आरंभ हो गया है।

नए कदम

'समेकन' का डिजाइन क्लाउड आधारित, वेब सक्षम मानव संसाधन जानकारी प्रणाली के रूप में किया गया है जिसमें नवीनतम सुरक्षा और आईटी प्रकार्यों को समाहित किया गया

¹ हावार्ड बिजनेस पब्लिशिंग (हावार्ड बिजनेस स्कूल और उनके कॉर्पोरेट शिक्षण प्रखंड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के माध्यम से।

है। आईटी अवसंरचना के नवीकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कार्य मैसर्स केवेबमेकर को दिया गया, जो अनुसूची के अनुसार चल रहा है। ब्यूरो की नई वेबसाइट को मैसर्स केवेबमेकर ने विकसित किया है और वर्ष के दौरान इसे लाइव कर दिया गया। नवीनतम सुरक्षा उपायों से युक्त इस वेबसाइट में कई नए फीचर और डाटाबेस हैं जो निर्बाध यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष के दौरान कई निविदाएं जारी की जाती हैं, इसलिए मैसर्स एमएसटीसी की सेवाएं ली गईं ताकि अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षरों, टाइम स्टैम्पिंग और निविदा से संबद्ध सभी क्रियाकलापों हेतु लागिंग का प्रयोग करते हुए – ई-निविदा की प्रस्तुति हो सके। इसका अधिक्रय करने के बाद से ही चाहे जो भी रकम हो, सभी कोटेशन/निविदाएं केवल ई-निविदा पोर्टल पर ही संचालित की जाती हैं। महत्वपूर्ण स्टाफ सदस्यों को डिजिटल हस्ताक्षर दिए गए हैं।

प्रशासनिक

प्रशासनिक पक्ष को देखा जाए तो सुनिश्चितता और नियंत्रण के एक उपाय के रूप में ब्यूरो ने बाहरी लेखा-परीक्षकों से अर्द्ध-वार्षिक लेखा-परीक्षा आरंभ कराई। लेखा-परीक्षा में ब्यूरो की सभी प्राप्तियों और भुगतानों और इससे सम्बद्ध प्रक्रियाओं को दायरे में लिया जाता है।

एक अन्य गतिविधि यह भी रही कि मंत्रिमंडल की नियुक्तिकर्ता समिति ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं हेतु) अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्यों की कार्यावधि का समय 11 अप्रैल 2020 के बाद दो साल आगे के लिए बढ़ा दिया। बीमा कंपनियों के लिए विशेषज्ञ सदस्यों श्री जी. एन. वाजपेयी और श्री मैथ्यू वर्गीस के कार्यकाल को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया और श्री एन. एम. गोवर्धन की नियुक्ति सदस्य के रूप में की गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के लिए श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री ए. आर. रिजवी को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

लेखांकन और आंतरिक व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्तियों और भुगतान लेखे की लेखा-परीक्षा पूरी हुई और संबंधित क्षेत्रों के लिए भारतीय स्टेट बैंक, आईआरडीएआई और नाबार्ड से वर्ष 2019-20, 2020-21 के सभी दावों और वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानों को प्राप्त किया जा चुका है।

IV. नियुक्तियों हेतु संस्तुतियां

वर्ष 2020-21 में ब्यूरो ने विभिन्न अधिदेशित संस्थानों के लिए 38 रिक्तियों हेतु प्रक्रिया का संचालन वर्ष 2020-21 में ब्यूरो ने विभिन्न अधिदेशित संस्थानों की 38 रिक्तियों का कार्य संभाला। संस्था-अनुसार और पदानुसार संस्तुतियों के बारे में आगे बताया गया है। मोटे-तौर पर कहा जाए तो विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में ब्यूरो को उच्चतर संख्या में पदों के लिए संस्तुतियां करने का कार्य सौंपा गया, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक थी। प्रत्येक रिक्ति के लिए लगभग 4.6 का अनुपात रहा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्येक रिक्ति के लिए 5 अभ्यर्थियों के दिशानिर्देश के विचारार्थ दायरे के अनुरूप ही है। इन अधिदेशित संस्थानों में वार्तालाप हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के व्यवहारगत आकलन ब्यूरो द्वारा किए गए। निजी क्षेत्र से आने वाले सभी अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि का भी सत्यापन किया गया।

तालिका 1 : वर्ष 2020-21 में नियुक्तियों हेतु की गई संस्तुतियां

पदनाम	एफआई	पीएसबी	पीएसआईसी	कुल
अध्यक्ष	-	1	-	1
सीएमडी	1	-	2	3
डीएमडी	1	-	-	1
एमडी	-	3	1	4
एमडी तथा सीईओ	1	4	-	5
ईडी	-	15	-	15
जीएम और निदेशक	-	-	9	9
कुल जोड़	3	23	12	38

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यपालक निदेशक

सभी संभावित और स्पष्ट रिक्तियों के लिए ब्यूरो द्वारा अपनी स्थापना के बाद से ही संस्तुतियों की जा रही हैं और इसमें कोई भी बैकलॉग नहीं है। वर्ष 2020-21 में प्रत्येक रिक्ति के लिए अभ्यर्थियों का अनुपात विगत वर्ष के 2.56 की तुलना में इस वर्ष 1.87 रहा। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि वर्ष 2020-21 में कार्यपालक निदेशकों की रिक्तियां तो अधिक रहीं लेकिन पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम रही।

तालिका 2 : राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यपालक निदेशक हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित अभ्यर्थी	संस्तुत अभ्यर्थी
2016-17	18	45	45	18
2017-18	15	39	39	15
2018-19	17	44	44	17
2019-20	4*	4	4	4
2020-21	15	28	28	15

*अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पार्षिक स्थान-परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से भरे गए पद

भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक पद हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के प्रत्येक पद हेतु औसतन 8.5 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इस पद के लिए व्यवहारगत आकलन करने की प्रथा वर्ष 2020-21 से आरंभ की गई।

तालिका 3 : भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित अभ्यर्थी	संस्तुत अभ्यर्थी
2016-17	1	3	3	1
2017-18	1	10	10	1
2018-19	1	11	11	1
2019-20	1	17	17	1
2020-21	3	19	19	3

राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी :

राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद को दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से भरा जाता है। यद्यपि चार बड़े बैंकों के लिए पात्र आंतरिक अभ्यर्थियों के साथ-साथ खुले बाजार से भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों अन्य छोटे बैंकों के मामले में चयन को केवल आंतरिक अभ्यर्थियों तक ही परिसीमित रखा जाता है। अन्य मामलों की तरह ही सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए व्यवहारगत आकलन किया जाता है। तथापि, निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु पृष्ठभूमि सत्यापन किया जाता है।

तालिका 4: राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित	व्यवहारगत आकलन	पृष्ठभूमि सत्यापन*	संस्तुत अभ्यर्थी
2016-17	3	10	10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3
2017-18	5	15	15	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5
2018-19	12	30	30	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	12
2019-20	4	62	25	25	9	4
2020-21	4	92	31	31	9	4

*केवल निजी क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों हेतु अनुमेय

भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष

भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष के पद हेतु इसी बैंक के केवल चार एमडी पात्र थे, जो रिक्ति की तारीख को बैंक की सेवा में रहेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकी।

तालिका 5 : भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित अभ्यर्थी	संस्तुत अभ्यर्थी
2017-18	1	4	4	1
2018-19	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-
2020-21	1	4	4	1

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष : ब्यूरो द्वारा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के पदों हेतु भी सुसंगत अनुभव और विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की संस्तुति की जाती रही है। ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वर्तमान रिक्तियों के लिए एनईसी की नियुक्ति के मामले में सक्रिय रूप से अनुसरण किया जा रहा है।

एफआई में अध्यक्ष / एमडी

वित्तीय संस्थानों में अध्यक्ष के पदों को खुले विज्ञापन के माध्यम से भरा जाता है। इनमें से प्रत्येक पद के लिए औसतन 14 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।

तालिका 6 : एफआई में अध्यक्ष / एमडी हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित	व्यवहारगत आकलन	पृष्ठभूमि सत्यापन*	संस्तुत अभ्यर्थी
2019-20	2	37	24	24	1	2
2020-21	2	51	33	33	33	2

वित्तीय संस्थाओं में डीएमडी

एफ आई के डीएमडी पदों को खुले विज्ञापन के माध्यम से भरा जाता है। इनमें से प्रत्येक पद के लिए औसतन 7 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।

तालिका 7 : एफ आई के डीएमडी हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित	व्यवहारगत आकलन	पृष्ठभूमि सत्यापन*	संस्तुत अभ्यर्थी
2019-20	7	116	40	25	0	2
2020-21	1	23	16	16	4*	1

* पृष्ठभूमि सत्यापन केवल निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष बीमा कंपनियों में अन्य पद

वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का पद पात्रता की शर्तें पूरी करने के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशकों में से भरा जाता है। अन्य बीमा कम्पनियों के सीएमडी हेतु भी इसी प्रकार के दिशानिर्देश यह बताते हैं कि ऐसे पदों को पात्र जोनल प्रबंधको / जेडएम और निदेशकों, आदि में से भरा जाएगा। सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में पदों के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों का व्यवहारगत आकलन करने की प्रथा वर्ष 2020-21 में आरंभ हुई।

तालिका 8 : भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित	संस्तुत अभ्यर्थी
2018-19	1	5	5	1
2019-20	-	-	-	-
2020-21	-	-	-	-

तालिका 9 : सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित	व्यवहारगत आकलन	संस्तुत अभ्यर्थी
2019-20	2	7	7	0	2
2020-21	2	10	10	10	2

तालिका 10 : भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशकों हेतु संस्तुतियां

अवधि	रिक्ति	आवेदक	चयनित	व्यवहारगत आकलन	संस्तुत अभ्यर्थी
2018-19	2	9	9	0	2
2019-20	2	7	7	0	2
2020-21	1	5	5	5	1

V. नवीन प्रयास

यह ब्यूरो दिए गए अधिदेश के परिप्रेक्ष्य में अपनी कार्यपद्धति की नियमित रूप से समीक्षा करता रहा है ताकि यह अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए उपाय कर सके। इस दिशा में ब्यूरो ने कई दूरगामी संस्तुतियां की हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार रही हैं – अधिदेशित संस्थानों के निदेशकों के विकास हेतु कार्यक्रम और उनके अधिकारियों के लिए डाटाबेस तैयार करना। इन निर्णयों को कार्यान्वित करने की दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख आगे किया जा रहा है :

निदेशकों हेतु परिवर्धन कार्यक्रम

ब्यूरो को अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिदेश भी मिला हुआ है कि बैंकों के लिए समुचित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार को परामर्श दे। इस अधिदेश के अनुसरण में ब्यूरो ने कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में विचार विमर्श किया ताकि अधिदेशित संस्थानों के बोर्डों को समर्थन दिया जा सके। यह अनुभव किया गया कि बोर्डों के सदस्य अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए उच्च-कोटि के कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।



इस दिशा में 28 अगस्त 2020 को आयोजित 34वीं बैठक में ब्यूरो के समक्ष एक विमर्श आलेख प्रस्तुत किया गया, और इसके बाद 5 अक्टूबर 2020 को आयोजित 37वीं बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो ने यह सिफारिश की कि यद्यपि इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने के लिए यह स्पष्ट प्रकरण है तथापि इसके डिजाइन में प्रयोक्ता के दृष्टिकोण को अपनाया जाए। ब्यूरो ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें प्रशिक्षण कला, विषयवस्तु, आदि का विवरण दिया गया।

कार्यक्रम आरंभ करने हेतु संस्तुति और इसके व्यापक डिजाइन-परिरेखा को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (आईबीए के मंच के माध्यम से) और एफआई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को आईबीए की प्रबंधन समिति ने 20 नवम्बर 2020 को अनुमोदन प्रदान किया, और इसके बाद कार्यक्रम की डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और आरंभिक निगरानी हेतु एक स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया।

ई-निविदा / प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी बोली लगाने के बाद छह पार्टियों की बोली को तकनीकी रूप से पात्र पाया गया जिनमें से तीन ने वाणिज्यिक नीलामी बोली तुलना हेतु योग्यता पाई। स्टीयरिंग समिति की चार अवसरों पर बैठक हुई ताकि समग्र प्रक्रिया को पूरा किया जा सके,

समिति ने पाया कि मैसर्स इगोन जेहन्डर इन्टरनेशनल प्रा. लि. (हावाई बिजनेस पब्लिकेशन्स लि. की साझेदारी में) का कार्यक्रम डिजाइन और प्रस्ताव सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

इस कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नामिती निदेशकों सहित सभी निदेशकों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तीन माड्यूल हैं यथा अभिप्रेरण, अभिमुखीकरण और पुनश्चर्या। इनमें से प्रत्येक माड्यूल को तीन माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा, यथा - हावाई बिजनेस पब्लिकेशन्स पोर्टल (15-20 घंटे की सामग्री), ऑनलाइन माध्यम से सेमिनार (चार दिन के समतुल्य) और व्यक्तिशः संवाद-मूलक विधि (तीन दिन)। इस समूचे कोर्सवेयर में आलेख, पॉडकास्ट, व्यक्तिगत अध्ययन, अनुकृति और अनुप्रयोग क्रियाकलापों, भूमिका निर्वाह, अनौपचारिक वार्ताएं और उद्योग की अंतः क्रियाएं शामिल की जाएंगी। इस कार्यक्रम का अधिशासन ऑनलाइन माध्यम से की गई डिलीवरी, सर्वेक्षणों, प्रश्नों और समीक्षाओं की ट्रेकिंग करते हुए वास्तविक प्रगति पर आधारित रहेगा।

यह कार्यक्रम किसके लिए है :

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों हेतु
(बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक, नामिती निदेशक – सरकार / नियामक,
स्वतंत्र निदेशक/ गैर-कार्यालयीन निदेशक या अन्य निदेशक)

आरंभ

सन 2021 की दूसरी छमाही
में आरंभ करने की अनुसूची
बनाई गई है

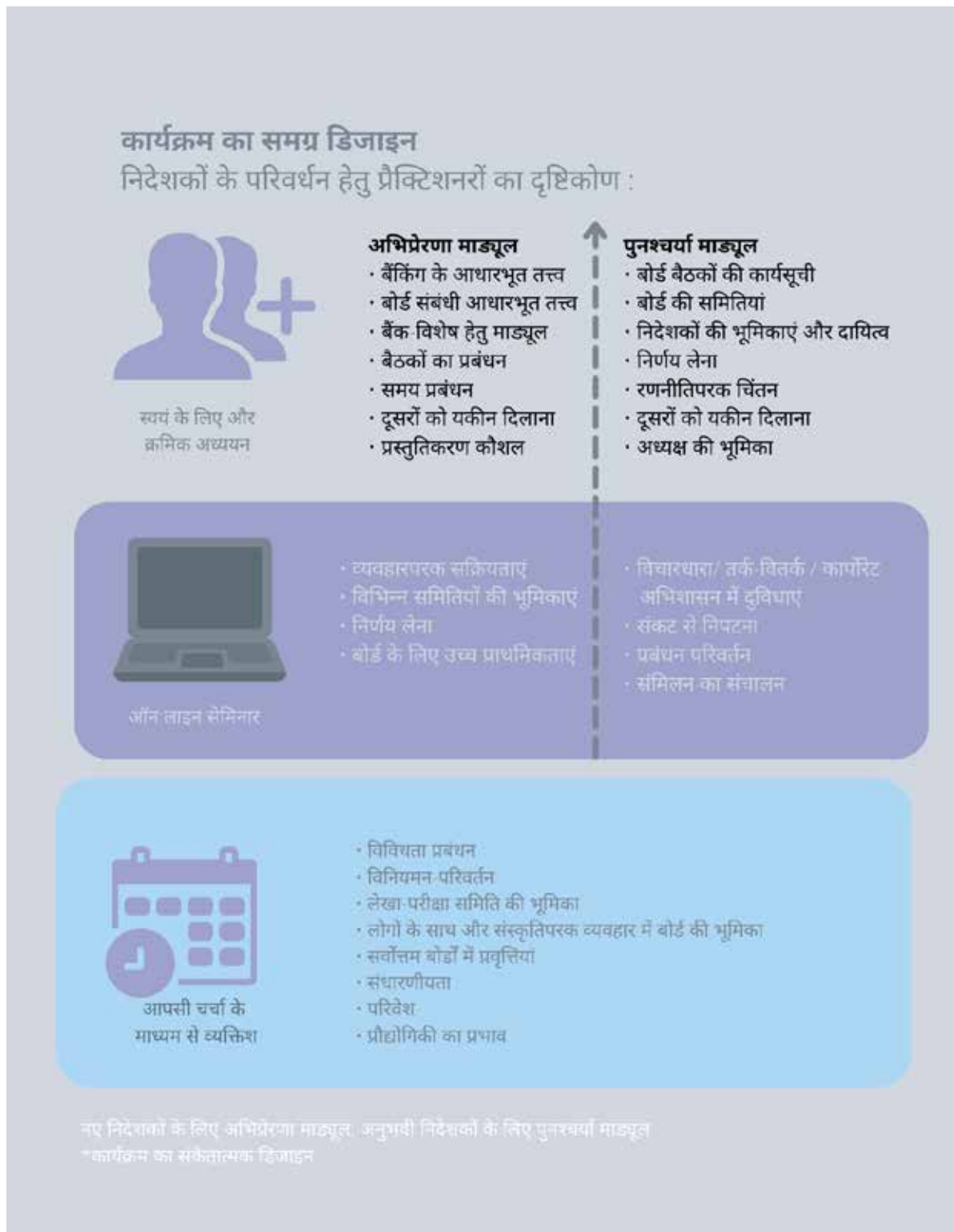
महत्वपूर्ण उद्देश्य :

- कापोरेट अभिशासन के सिद्धांतों का अधिमूल्यन और प्रभावी संस्था का निर्माण करने में इनका अनुप्रयोग।
- अभिशासन, उद्यमिता और प्रबंधन में निदेशक की भूमिका के अधिमूल्यन का सृजन
- स्ट्रेकधारकों के प्रबंधन और कार्यनिष्पादन डिलीवरी में नेतृत्व और संस्थापरक समस्याओं की समझ पैदा करना।
- शेष बोर्ड के साथ-साथ समग्र संस्थान के साथ उनके कामकाज करने की प्रभावशीलता को अधिकतम करने में सक्षमता की समझ का सृजन करना।
- वित्तीय बाजारों, विनियमों और संविधियों, ग्राहक व्यवहारों, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा, फिनटेक, आदि में नवीनतम गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करना
- प्रभावी निदेशक हेतु अनिवार्य लक्षणों का विकास करना

निदेशकों के परिवर्धन हेतु कार्यक्रम में यह कल्पना की गई है कि वे अपने बारे में निम्नलिखित त्वरित प्रश्नों के उत्तर तैयार रखें

क्या आप जानते हैं	क्या आपके पास	क्या आप	यदि ऐसा हो जाए
कि अपने उद्योग, बैंक, विनियमों, विधिक परिवेश के बारे में क्या जानने की जरूरत है।	ऐसा अनुभव है जो कारोबार और भावी जरूरतों के अनुकूल है।	प्रभावी बने रहने के लिए अपनी क्षमता निरंतर बढ़ाते रहते हैं।	दबाव और संकट के समय आपकी क्या पद्धति रहेगी।
कि उदीयमान कारोबार, ग्राहक, प्रौद्योगिकी की प्रवृत्ति कारोबार को किस प्रकार से प्रभावित करेगी।	ऐसी नेतृत्व क्षमता है जो वर्तमान और भावी भूमिका निर्वाह के अनुकूल है।	जटिल और परिवर्तनशील कारोबार के प्रति सचेत रहते हैं।	रणनीति और संचालन संबंधी दुविधाओं से कैसे निपटेंगे।
	अपनी भूमिका के संबंध में चुनौतियों को समझते और सही मूल्यांकन करते हैं।	सभी भीतरी और बाहरी हिस्सेदारों को एकजुट रखते हुए प्रेरित कर सकते हैं।	भिन्न दृष्टिकोणों और परिप्रेक्ष्यों के समय क्या सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है।
	अपने बैंक और इसके हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके प्रतिमानों के अनुकूल हैं।	गड़बड़ी के समय और विरोध के बावजूद भी सुस्थिर रह सकते हैं।	
ज्ञान	दक्षता	व्यावहारिक अनुप्रयोग	चुनौतियां दुविधाएं

कार्यक्रम डिजाइन के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण इस प्रकार हैं :



इस कार्यक्रम की डिजाइन में काफी प्रगति हो चुकी है और शीघ्र ही आरंभ होने की प्रत्याशा है।

समेकन (SAMEKAN)

ब्यूरो को मिले हुए अधिदेशों में से एक यह भी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के कार्यनिष्पादन के बारे में एक डाटाबेस रखा जाए। इस डाटाबेस को तैयार करने की प्रविधि के बारे में बोर्ड की जनवरी 2021 में हुई बैठक में चर्चा की गई थी। यह महसूस किया गया कि डाटाबेस का डिजाइन ऐसा हो जो बोर्ड को न केवल अधिकारियों के कार्यनिष्पादन / प्रमाणिकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करे बल्कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भी अपने मानव संसाधन विश्लेषणों के बारे में सहायता दे और इसी क्रम में वे अपनी प्रणाली में भी इसके कुछ तत्वों को समाहित करें। इसी क्रम में – प्रबंधन और कर्मचारी सेवा और ज्ञान विषयक तथ्यों का समाहार और विश्लेषण प्रणाली – अर्थात् समेकन नाम से वेब अनुप्रयोग हेतु सिस्टम अपेक्षाओं का अध्ययन किया गया।

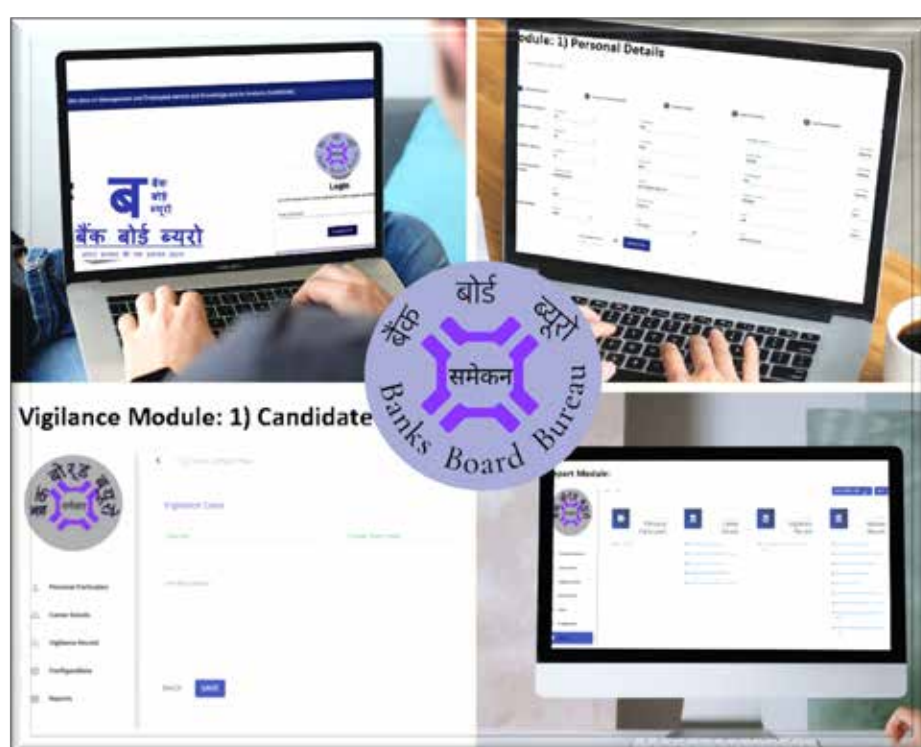


सॉफ्टवेयर विकास और प्रदेय की आंतरिक क्षमता वाले सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से सम्पर्क करने के बाद यह निर्णय किया गया कि इस सिस्टम का डिजाइन और विकास भारतीय स्टेट बैंक करेगा, जिसने सर्व-कल्याण हेतु इसका विकास करने की सहमति दी है। इसलिए यह कार्य बेलपुर में स्थित एसबीआई ग्लोबल आईटी सेन्टर (गिटसी) को सौंप दिया गया।

आईटी अवसंरचना की स्थापना और प्रबंधन का कार्य बाहरी मैसर्स के वेबमेकर को दिया

गया है। समस्त वेब अनुप्रयोग, वेब सेवाएं और डाटाबेस को क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा और इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक के सुरक्षा मानकों को भी पूरा करे।

प्रयोजनमूलक स्तर पर समेकन में पाँच प्रमुख माड्यूल हैं जो व्यक्तिगत विवरण, प्रशिक्षण और शिक्षा, पोस्टिंग और स्थानांतरणों, पदोन्नतियों, सतर्कता प्रोफाइल, कार्य निर्धारण, मानक रिपोर्ट और बेन्चमार्क, आदि। इस वेब अनुप्रयोग में नवीनतम कूटलेखन और सत्यापन व्यवस्था का प्रयोग किया गया है ताकि डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। डाटाबेस में यह प्रत्याशित है कि एक ही स्थल पर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों का समेकित प्रालेख प्रदान करे और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से भी किसी एक बैंक के बारे में मानव संसाधन बेंचमार्क प्रदान करे।

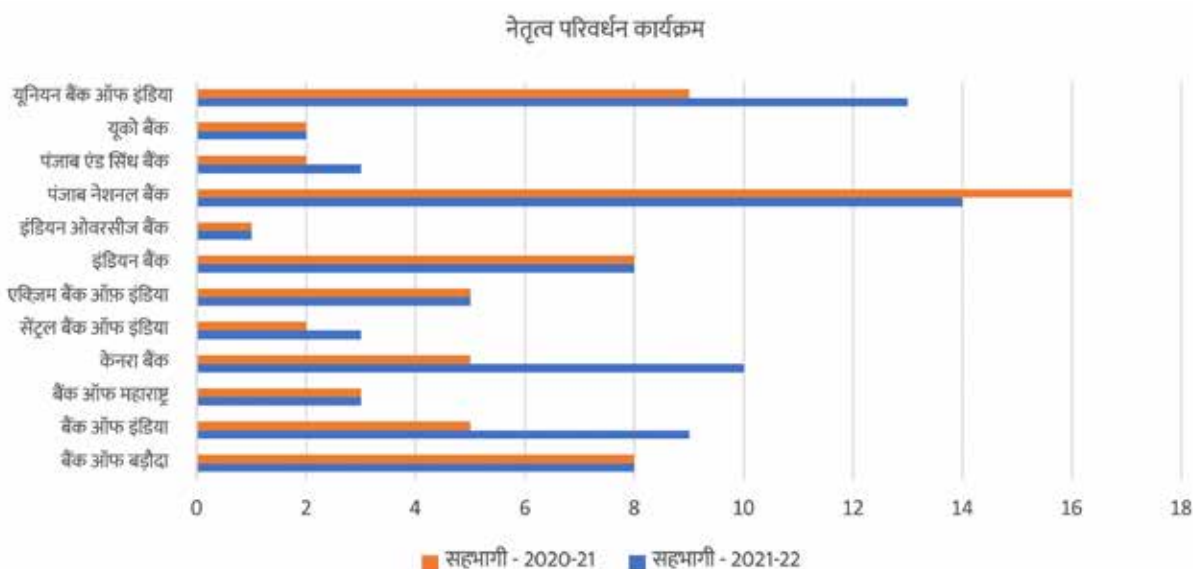


इससे बोर्ड स्तर की रिक्तियों के लिए व्यक्तियों के आकलन में सहायता तो मिलेगी ही, साथ-साथ यह सभी प्रशासनिक और एचआर संबद्ध प्रकार्यों के लिए सिस्टम में समाहित डाटा के लिए एकल-स्थलीय उपादान के रूप में भी कार्य करेगा। यह परियोजना समय पर है और आशा है कि वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में लाइव हो जाएगी।



नेतृत्व परिवर्धन कार्यक्रम

एलडीपी के प्रथम बैच में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 78 उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक शामिल थे, जिसका समापन 17 जुलाई 2020 को हुआ जो 19 जुलाई 2019 को सभी माँड्यूलों के साथ आरम्भ किया गया था।



प्रत्येक मध्यवर्तन के बाद आईआईएम बंगलोर द्वारा संग्रहीत सहभागियों से लिए फीडबैक से संतोष के उच्च स्तर का संकेत मिलता है। सहभागियों से सर्वेक्षण के अलावा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से 359 अधिकारियों से संरचनाबद्ध प्रश्नावली के माध्यम से भी सर्वेक्षण किया गया। प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ व्यावसायिक संबंधों यथा - अधीनस्थ, सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी के आधार पर इन अधिकारियों का अभिनिर्धारण किया गया। अधिकांश प्रतिसादियों ने, अपने व्यावसायिक संबंधों पर ध्यान दिए बिना ही सहभागियों में उच्च स्तरीय सुधार का अवलोकन किया। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों द्वारा 'लाइव प्रोजेक्ट' के प्रभाव का आकलन रु.4,265 करोड़ रहा।

द्वितीय बैच 11 सितम्बर 2020 से आरंभ हुआ जिसमें एक्जिम बैंक सहित 12 बैंकों से 66 सहभागियों को शामिल किया गया। कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण प्रोग्राम के सभी मॉड्यूलों को ऑनलाइन ही प्रदान किया गया। सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग बैंकों और एक्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों द्वारा किए गए आकलनों के अनुसार लाइव प्रोजेक्टों के कारण कुल मिलाकर लगभग रु.4,122 करोड़ की बचत हुई। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक्जिम बैंक से 79 सहभागियों के प्रशिक्षण का तृतीय बैच 16 अगस्त 2021 से शुरू हुआ।

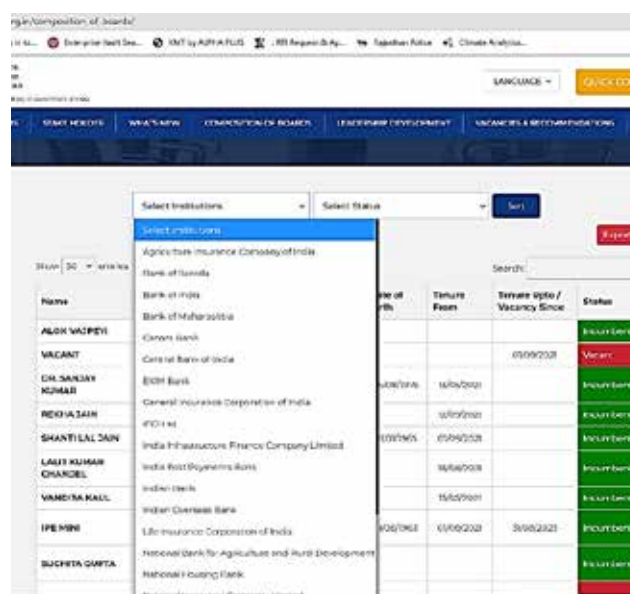
VI. डाटाबेस, आईटी प्रणाली और प्रशासनिक कार्य

बहुत ही कम स्टाफ संख्या के साथ ब्यूरो का कार्यालय मुम्बई में है, और कार्य-चालन को सुगम बनाने के लिए आईटी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। महामारी के हालात में कार्य करने की इन सुविधाओं को और भी बढ़ाया गया ताकि प्रक्रियाओं और साइबर सुरक्षा के संबंध में कोई समझौता किए बिना ही सहज कार्य-चालन सुनिश्चित किया जा सके। विश्लेषणात्मक पक्ष को देखा जाए तो ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति का तिमाही विश्लेषण निरंतर बनाए रखा। वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर कुछ नई सुविधाओं और सिस्टम का कार्यान्वयन किया गया जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है।

वीडियो सम्मेलन सुविधा

महामारी के इस हालात ने यह अनिवार्य कर दिया कि ऐसी प्रभावी वीसी सुविधा का क्रय किया जाए जिसकी सहायता से ब्यूरो अपने साक्षात्कारों का आयोजन निर्धारित पद्धति के अनुसार कर सके। सिसको वेबएक्स के आधिकारिक उत्पादों और सेवाओं के साझीदार टाटा कम्यूनिकेशंस के साथ गहन विचार-विमर्श और आजमाइश के बाद सिसको वेबएक्स के लिए यूजर लाइसेन्स लिए गए। ब्यूरो ने बैठकों और आपसी विमर्श के लिए ऑनलाइन मोड में मदद के लिए प्रोटोकॉल और अन्य प्रलेखन को तैयार किया और उसका कार्यान्वयन भी किया। प्रलेखों पर ई-हस्ताक्षर हेतु भी सचिवालय ने क्षमताएं हासिल की गईं।

बोर्डों के गठन के बारे में डाटाबेस



Name	Institution	Tenure From	Tenure upto / Vacancy Since	Status
ALOK KASHYAP	Bank of India		09/09/2021	Incumbent
VACANT	Bank of Maharashtra			Vacant
DR. SANJAY KUMAR	Central Bank of India			Incumbent
REKHA SAH	ICICI Bank	01/01/2018	01/01/2021	Incumbent
SHANTILAL DAIN	Central Insurance Corporation of India	01/01/2018	01/01/2021	Incumbent
LAJEET KUMAR CHANDLER	India Infrastructure Finance Company Limited	01/01/2018	01/01/2021	Incumbent
VANDANA KALL	India Post Payments Bank	01/01/2018	01/01/2021	Incumbent
IPR NING	Indian Overseas Bank	01/01/2018	01/01/2021	Incumbent
BUCHITA DARTIA	Life Insurance Corporation of India	01/01/2018	01/01/2021	Incumbent
	National Bank for Agriculture and Rural Development			Incumbent
	National Housing Bank			Incumbent
	National Insurance Company Limited			Incumbent

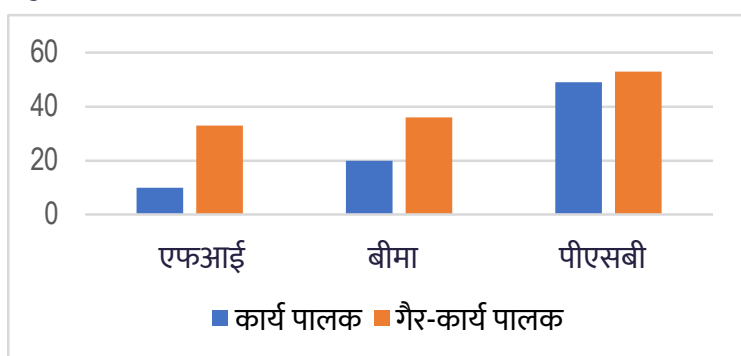
इस ब्यूरो को यह अधिदेश दिया गया है कि यह अधिदेशित संस्थाओं के बोर्डों के गठन के बारे में डाटाबेस का रखरखाव भी करे। अभी तक इस प्रकार डाटाबेस एक्सेल में रखा जाता था, जिसके माध्यम से विश्लेषण और प्रकटीकरण सहज नहीं था। समस्त प्रक्रिया को

सहज और सरल बनाने के लिए बोर्डों के गठन के बारे में ऑनलाइन डाटाबेस का सृजन वेब अनुप्रयोग करते हुए किया गया जो कॉन्टेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम (सीएमएस) के साथ एकीकृत किया गया। यह वेब अनुप्रयोग साइट सुक्यूरी के साथ सुरक्षित किया गया है जो हर समय इसे सुरक्षा, निगरानी और बैकअप प्रदान करती है। सीएमएस की सहायता से ब्यूरो सुरक्षित इन्टरफेस के माध्यम से डाटाबेस का रखरखाव करता है।

यह डाटाबेस ब्यूरो की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया हुआ है जो प्रयोक्ता को रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति देता है, जिसमें रिक्त पदों के अलावा पदधारी और सेवानिवृत्त बोर्ड सदस्यों, उनके कार्यकाल, आदि को भी दर्शाया जाता है। प्रयोक्ता ऐसी विशेष रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है जिसमें ऐसे व्यक्तियों की संस्था-अनुसार सूची भी हो जो अगले छह माह में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। प्रयोक्ता के पास यह विकल्प भी है कि वह फिल्पों का प्रयोग करते हुए अन्य रिपोर्टें भी तैयार कर सकता है। सचिवालय द्वारा इस डाटा को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, ताकि प्रचलन सुनिश्चित हो सके।

ब्यूरो के अधिदेश के अधीन संस्थाएं

ब्यूरो को राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, एनएचबी, आईएफसीआई लिमिटेड, आईआईएफसीएल और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में बोर्ड स्तरीय पदों के लिए व्यक्तियों की संस्तुति करने का कार्य सौंपा गया है।



संस्थाओं की श्रेणी	नम्बर
पीएसबी (आईपीपीबी के साथ)	13
पीएससी	7
एफ आई	6

अधिदेशित संस्थाओं के बोर्डों के गठन के संबंध में देखा जाए तो वर्तमान में सामान्यतया सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में गैर-कार्यपालक और कार्यपालक सदस्यों की समान रूप से मौजूदगी है। दूसरी तरफ, समग्रतया वर्तमान में बीमा कंपनियों, सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में गैर-कार्यपालक सदस्यों की संख्या अधिक ही होती है।

ब्यूरो की नई वेबसाइट

ब्यूरो की नई वेबसाइट दिसम्बर 2020 से लाइव हुई। इस क्लाउड वेबसाइट का डिजाइन, होस्टिंग और सुरक्षा नवीनतम टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यह वर्डप्रेस आधारित कॉन्टेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम के साथ एकीकृत की गई है जो सचिवालय को यह सुविधा देता है कि किसी भी बाहरी वेन्डर पर निर्भरता के बिना ही इसकी विषयवस्तु को नवीनतम बना सके। यह वेबसाइट सर्वेम्सकी के साथ भी एकीकृत की गई है जो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने में सहायक है, साथ में ट्विटर के संदेशों को दर्शाने के लिए बोर्ड का अपना सत्यापित हैंडल (@BanksBoardBuro) भी है, MySQL के माध्यम से बोर्डों के गठन पर डाटाबेस का रखरखाव किया जाता है, फायरवॉल भी है साथ में गूगल एनालिटिक्स, आदि भी हैं।

ट्विटर हैंडल

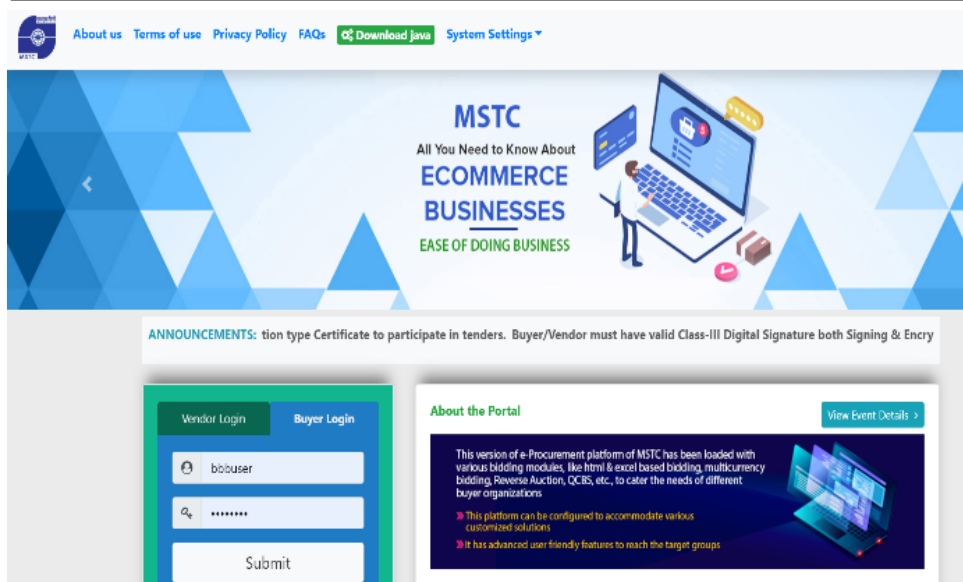
बैंक बोर्ड ब्यूरो के सत्यापित ट्विटर हैंडल @BanksBoardBuro को ब्यूरो की नई वेबसाइट पर भी लाइव कर दिया गया। यह हैंडल वेबसाइट के साथ एकीकृत है, इसलिए दोनों में से किसी भी स्रोत पर प्रकाशित किसी भी नोटिस और सूचना से प्रयोक्ता चूके नहीं। इसके आरंभ से ही सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, निविदा नोटिस, अनुप्रयोग, संस्तुतियों, आदि को ट्विटर हैंडल और प्रमुख वेबसाइट पर एक साथ प्रकाशित किया जाता है।



ई-निविदा पोर्टल

यह ब्यूरो विभिन्न सेवाओं के अधिक्रय हेतु कोटेशन मंगाने के लिए निविदाएं जारी करता रहा है। मुख्य सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करने के उद्देश्य से अब ब्यूरो ने मैसर्स एमएसटीसी लि. के ई-अधिक्रय पोर्टल पर स्वयं को संस्थापित करा लिया है।

यह पोर्टल पूर्णतया सुरक्षित ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली प्रदान करता है। मूल्य पर कोई विचार किए बिना ही ब्यूरो द्वारा अधिक्रय हेतु सभी निविदा प्रक्रियाएं 12 जनवरी 2021 के बाद से इसी पोर्टल पर की जाती हैं। ब्यूरो के पाँच में से चार अधिकारियों ने इस प्रयोजन हेतु



ई-मुद्रा से वर्ग-3 के डिजिटल प्रमाणपत्र ले लिए हैं।

सूचना का अधिकार

वर्ष 2020-21 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए इस ब्यूरो को 12 अनुरोध और 4 अपीलें प्राप्त हुईं। एक मामला द्वितीय अपील के रूप में मुख्य सूचना आयोग के पास तक गया जिसे खारिज कर दिया गया। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई और कोलकाता में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस ब्यूरो का समस्त स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से है, इसलिए ये कार्यक्रम उनके लिए भी उपलब्ध थे।

ब्यूरो को पहले की ही तरह से केवल भौतिक रूप में ही आरटीआई आवेदन मिलते रहे, क्योंकि आरटीआई के लोक पोर्टल पर सूचीबद्ध नहीं है। ब्यूरो को सरकारी प्राधिकरणों हेतु आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल ऑनबोर्ड किया गया और 5 मार्च 2021 को इसे लाइव कर दिया गया और तब से प्राप्ति, प्रतिसाद, अपील से संबद्ध सभी प्रक्रियाएं अब इसी पोर्टल पर ऑनलाइन की जा रही हैं। अब आम जनता के लोग भी www.rtionline.gov.in के माध्यम से आरटीआई के आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ब्यूरो द्वारा अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रेरणा से ही सभी प्रकटीकरण किए जा रहे हैं। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे को पारदर्शिता ऑडिटर रखा गया है। प्रथम ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत की जा चुकी है।

ब्यूरो की दो समितियां हैं यथा – स्वतः प्रेरणा से प्रकटीकरण विषयक परामर्श समिति और दूसरी समिति आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी का अभिनिर्धारण करने हेतु। इन समितियों की संस्तुतियों को ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रकटीकरण में विधिवत समाहित किया गया है।

VII. प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां : वर्तमान में ब्यूरो की परिधि में आने वाले सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं से आने वाली रकम इस ब्यूरो की प्राप्तियों में है। होने वाले व्यय (किए गए और अनुमानित) को संस्थानों के अलग-अलग वर्गों में यथा – सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के बीच ब्यूरो द्वारा सेवित रिक्तियों के समानुपात में विभाजित किया जाता है। प्रचलित निदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए नोडल संस्था भारतीय स्टेट बैंक है, बीमा कंपनियों के आईआरडीएआई और वित्तीय संस्थानों के लिए नाबार्ड है।

भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड और भारतीय जीवन बीमा निगम (आईआरडीएआई के अनुसार नोडल संस्था) से वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए सभी देय रकम प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार ब्यूरो से अपेक्षित है कि व्यय का अनुमान लगाए और इसे उस वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्तियों के समानुपात में सभी संस्थाओं के बीच वितरित करे। तदनुसार ब्यूरो ने वर्ष 2021-22 के लिए व्यय हेतु अपने अनुमान तैयार किए और भारतीय स्टेट बैंक, आईआरडीएआई तथा नाबार्ड को अपनी मांग भेज दी है। इन सभी संस्थाओं से सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुके हैं।

ब्यूरो की प्राप्तियों और भुगतानों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे गए खातों के माध्यम से निष्पन्न किया जाता है।

भुगतान : प्रमुख भुगतानों का संबंध मुंबई में लीज-किराए और कार्मिकों पर आने वाली लागत के लिए किया जाता है, जिनकी प्रतिपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक को की जाती है। ब्यूरो के लिए ये व्यय आवर्ती व्यय के तौर पर हैं। बाहरी एचआर एजेंसी के शुल्क अभ्यर्थियों के आकलन और पृष्ठभूमि सत्यापन हेतु दिए जाते हैं। इसके पास कोई स्थायी आस्तियां नहीं हैं क्योंकि सभी फिक्सचर्स, फर्नीचर और कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि भारतीय रिज़र्व बैंक प्रदत्त हैं। हार्डवेयर की छोटी मदों पर हुए व्यय को राजस्व व्यय माना जाता है।

निपुणता की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिभा अधिग्रहण लागत (कुल व्यय को रिक्तियों की संख्या से विभाजित करके) वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक रिक्ति के लिए केवल ₹ 2.44 लाख रही, इसकी तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रत्येक रिक्ति पर ₹ 17.4 लाख का व्यय हुआ।

यह कमी मुख्य रूप से आकलित अभ्यर्थियों की उच्चतर संख्या के कारण रहा जिसमें निश्चित व्यय में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई और केवल परिवर्तनशील व्ययों में समानुपातिक बढ़ोतरी हुई।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण

भुगतान				प्राप्तियां			
विवरण	राशि	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	विवरण	राशि	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
विज्ञापन		73,08,882	32,83,510	2020-21 के लिए बकाया प्राप्तियां	2,06,34,952		
कार्मिक		1,53,73,330	1,46,49,473	नाबार्ड से प्राप्त रकम को घटा कर	1,56,38,108		1,06,41,265
किराया		63,90,000	63,90,000	एलआईसी से प्राप्त रकम को घटा कर	49,96,844		2,06,34,952
यात्रा / विराम				2021-22 के लिए प्राप्त प्रतिपूर्तियां			
किराया	1,90,345			भारतीय स्टेट बैंक	1,43,44,342		
होटल	32,878			एलआईसी	1,48,07,557		
कार किराए पर लेना	20,686	2,43,909	15,55,485	नाबार्ड	32,39,100	3,23,90,999	
एचआर एजेन्सियां		82,75,340	18,46,700	2020-21 के लिए बकाया प्राप्तियां नाबार्ड से प्राप्त रकम को घटा कर एलआईसी से प्राप्त रकम को घटा कर 2021-22 के लिए प्राप्त प्रतिपूर्तियां भारतीय स्टेट बैंक एलआईसी नाबार्ड		1,01,49,026	
सिटिंग प्रभार							
पीएसआईसी सदस्य	9,50,000						
पीएसबी/ एफआई सदस्य	23,50,000	33,00,000	19,70,000				
आस्तियों की खरीद		-	4,01,760				
सॉफ्टवेयर		9,28,142	97,451				
पोस्टेज, उपभोज्य वस्तुएं		5,05,597	2,77,236				
विविध		2,14,825	1,44,391				
कुल		4,25,40,025	3,12,76,217			4,25,40,025	3,12,76,217

**एससीए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार**

बी104-, कनकिया जिलियन, बीकेसी
एनेक्सी, एलबीएस/ सीएसटी रोड जंक्शन,
कुर्ला बस डिपो के पास, कुर्ला पश्चिम, मुंबई-
400070,
फोन 62450777-
[ईमेल-mail@scaassociates.com](mailto:mail@scaassociates.com)
वेबसाइट-
www.scaandassociates.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सचिव

बैंक बोर्ड ब्यूरो

अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स बैंक बोर्ड ब्यूरो की प्राप्तियों और भुगतानों (विवरण) के विवरण की लेखा परीक्षा की। इस विवरण को बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्रबंधन वर्ग द्वारा तैयार किया गया ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किए गए भुगतानों और तदनुसूची प्राप्तियों / होने वाली प्राप्तियों की सत्य और उचित प्रस्तुति की जा सके।
2. हमारे अभिमत से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक बोर्ड ब्यूरो की प्राप्तियों और भुगतानों के बारे में इस विवरण में सत्य और उचित प्रस्तुति है।

अभिमत हेतु आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के आधार पर की। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के विवरण खंड के लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्वों में दिए गए हैं। आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता संहिता का अनुसरण करते हुए हम बैंक बोर्ड ब्यूरो से स्वतंत्र हैं और हमने इस नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को भी पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखा परीक्षा के जो भी साक्ष्य हमने प्राप्त किए वे हमारे अभिमत हेतु पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

4. इस विवरण को तैयार करने और उचित प्रस्तुति का दायित्व बैंक बोर्ड ब्यूरो का है ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो के भुगतानों और उनके समानुरूप प्राप्तियों का सत्य और उचित प्रकटीकरण हो सके। इस दायित्व में पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव और विवरण को तैयार करने और उचित प्रस्तुति हेतु सुसंबद्ध आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं जिससे कि यह विवरणी धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण किसी भी वास्तविक अपविवरण से मुक्त है।

विवरण की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का दायित्व

5. हमारा उद्देश्य है कि इस बारे में समुचित भरोसा प्राप्त करें कि समग्र रूप से यह विवरण सभी प्रकार के वास्तविक अपविवरणों से मुक्त है, चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो सकता हो या त्रुटि के

कारण, और फिर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करें जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। पर्याप्त सुनिश्चितता एक प्रकार से उच्च स्तरीय सुनिश्चितता होती है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में जब भी कोई वास्तविक अपविवरण हुआ है तो हमेशा ही कोई वास्तविक अपविवरण पकड़ में आएगा। किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण अपविवरण हो सकते हैं, और इन्हें वास्तविक माना जाता है, यदि अलग-अलग अथवा सम्यक तौर पर इस विवरण के आधार पर प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर पर्याप्त रूप से प्रभाव पड़ना प्रत्याशित हो।

6. लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के तौर पर हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयवाद बरकरार रहता है। हम वक्तव्य में वास्तविक अपविवरण के जोखिम को भी अभिनिर्धारित करते हैं और उसका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण अथवा त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा का प्रतिसादात्मक डिजाइन और निष्पादन करते हैं, और अपने अभिमत के आधार स्वरूप पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी से पैदा होने वाले वास्तविक अपविवरण को नहीं पकड़ पाने का जोखिम त्रुटियों के कारण होने वाले अपविवरण से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, अपप्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड करना निहित होता है।
7. इस लेखा परीक्षा हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की ताकि परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा पद्धति डिजाइन की जा सके।

8. विवरण अथवा प्रयोग पर प्रतिबंध

इसके साथ दिया जा रहा विवरण केवल बैंक बोर्ड ब्यूरो की जानकारी के लिए ही तैयार किया गया है और इसलिए यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए उचित नहीं हो सकेगा। यह रिपोर्ट केवल उपरोल्लिखित प्रयोजन से जारी की गई है और बिना हमारी लिखित सहमति के इसका किसी अन्य प्रयोजन या किसी अन्य पार्टी को संदर्भ अथवा विवरण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बिना हमारी लिखित सहमति के यदि किसी अन्य को यह रिपोर्ट दिखाई जाती है या उसके हाथ पड़ जाती है तो किसी अन्य प्रयोजन या अन्य व्यक्ति की वजह से हम किसी दायित्व को स्वीकार अथवा अंगीकार नहीं करेंगे।

कृते एसजीए एंड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 101174डब्ल्यू

ह/-

शिवरतन अग्रवाल

साझेदार

सदस्यता संख्या : 104180

यूडीआईएन : 21104180एएएईजी4933

मुम्बई – 17 मई 2021

बैंक्स बोर्ड ब्यूरो

BANKS BOARD BUREAU

4th floor, Reserve Bank of India
Byculla Office Building,
Mumbai Central,
Mumbai - 400 008

चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक,
डॉ आनंद राव नायर मार्ग, मुंबई सेंट्रल,
मुंबई - ४०० ००८

BANKS BOARD BUREAU

Annual Report

2020-21



**Directors
Development
Program**



Appointment



Assessments



Analytics



Contents

Chapter	Description	Pages
I.	The Banks Board Bureau	3
II.	Principal Officers of Secretariat	4
III.	Overview	5
IV.	Recommendation for Appointments	9
V.	New Initiatives	13
VI.	Databases, IT Systems and Administrative works	20
VII.	Receipts and Payments Account	24

LIST OF ABBREVIATIONS

CEO	Chief Executive Officer
CGM	Chief General Manager
CMD	Chairman and Managing Director
DDP	Directors Development Program
DFS	Department of Financial Services
DMD	Deputy Managing Director
FI	<i>See PSFI</i>
GM	General Manager
IBA	Indian Banks Association
IIFCL	India Infrastructure Finance Company Limited
IFCI	IFCI Ltd.
IPPB	India Post Payments Bank
IIM	Indian Institute of Management
LDP	Leadership Development Program
MD	Managing Director
MD & CEO	Managing Director and Chief Executive Officer
MOF	Ministry of Finance, Govt of India
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NEC	Non-Executive Chairman
NOD	Non-official Director
NRC	Nomination & Remuneration Committee
PSIC	Public Sector Insurance Company
PSB	Public Sector Bank
PSFI	Public Sector Financial Institution
RMCB	Risk Management Committee of Board
SEBI	Securities & Exchange Board of India
SIDBI	Small industries Development Bank of India
WTD	Whole Time Directors

BANKS BOARD BUREAU

COMPOSITION

Public Sector Banks & Financial Institutions

Public Sector Insurance Companies

Bhanu Pratap Sharma
Chairman

Debasish Panda
Secretary
Department of Financial Services
Ex-Officio Member

Debasish Panda
Secretary
Department of Financial Services
Ex-Officio Member

Ali Raza Rizvi[@]
Secretary Department of
Public Enterprises
Ex-Officio Member

Ali Raza Rizvi[@]
Secretary Department of
Public Enterprises
Ex-Officio Member

M. Rajeshwar Rao[#]
Deputy Governor
Reserve Bank of India
Ex-Officio Member

Dr. S C Khuntia[&]
Chairman, Insurance Regulatory &
Development Authority of India
Ex-Officio Member

Vedika Bhandarkar
Former Vice Chairman & MD
Credit Suisse
Expert Member

Ghyanendra Nath Bajpai^{*}
Former Chairman
SEBI and LIC of India
Expert Member

Pradeep Kumar Panja
Former MD
State Bank of India
Expert Member

N M Govardhan
Former Chairman
LIC of India
Expert Member

Pradip Panalal Shah
Founder MD
CRISIL
Expert Member

Mathew Verghese^{*}
Former General Manager
New India Assurance Company Ltd.
Expert Member

[@] Shri Sailesh was the Ex-Officio member upto March 31, 2021.

[#] Shri Mahesh Kumar Jain was the Ex-Officio Member upto November 11, 2020.

[&] Dr. S C Khuntia's term in IRDAI and consequential ex-officio membership was upto May 2021.

^{*} The term of these expert members got over on May 12, 2021.

II. PRINCIPAL OFFICERS OF SECRETARIAT

Secretary

Dr. Vijay Singh Shekhawat, General Manager

Assistant General Manager

Rishabh Garg

Manager

Prateek Jain

Assistant Managers

Devansh Rawat

Adithya M

III. OVERVIEW

It was a challenging year which began with the first wave of COVID-19 pandemic and ended with the resurgence of the second wave. It led to the imposition of a strict lockdown for a considerable period during the financial year. The Bureau office in Mumbai remained shut from March 2020 onwards and had to necessarily set up protocols for work from home. While routine work continued with some difficulty, new processes and protocols were needed for moving the works related to interactions online. The major consideration was to ensure that all the extant processes / guidelines were fully complied with while complying with physical and cyber safety protocols. The timely action taken by the Board enabled resumption of activities without losing any time.

Recommendation for Appointments

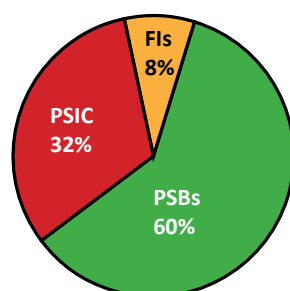
During this period, the Bureau held a record number of 19 meetings spread over 21 days and covered agenda relating to selection of personages as well as some very important ones on governance of PSBs, FIs and PSICs.

The Bureau interacted with 173 candidates thus maintaining an average ratio of five candidates per vacancy. All these interactions were done while maintaining pandemic related protocols. The Bureau also evolved mechanisms to continue with competency assessment and other checks for majority of the candidates appearing for any of the Board level positions in Public Sector Insurance Companies (PSICs), Public Sector Banks (PSBs), and Public Sector Financial Institutions (PSFIs). The Bureau also reviewed its processes for assessment of candidates and decided to introduce more stringent methods of assessment and application submissions. The revised process involved submission of a vigilance profile while the assessment methods were revised based on comprehensive competency assessment framework that aligns attributes to assessment criteria.

The Bureau made recommendations for appointment of 38 person-

ages, the breakup of which is as follows-

Number of Recommendations



Category	FIs	PSBs	PSICs	Total
Number of Recommendations	3	23	12	38

The average time for making the recommendations was 72 days. This average is the weighted average of the time taken for recommending positions in PSBs (76 days), in PSICs (36 days) and in FIs (189 days). The average time taken for recommendation for FIs was higher because all the vacancies had to be advertised, while in the case of insurance companies, the list of candidates for interaction was provided by the DFS based on the concept of zone of consideration and seniority. Looking at the average time through a different angle, it was 60 days when the vacancy was to be filled up by internal candidates while it was 180 days when the vacancies were filled through open advertisements. In the previous year, the average time for selection and appointment was less primarily because the PSB mergers taken up in that year resulted in several lateral movements of Directors within the PSBs which did not require any advertisement.

The Government had accepted all its 38 recommendations (100%) for appointments. The appointment process, which was done by the Department of Financial Services, took on an average 4.4 months from the date of Bureau's recommendation. This includes the time taken for the vetting processes and the time taken for the approval of the recommendation by the competent authority. Of the 38 appointments, four were notified prior to the date of vacancy.

Strategy Meetings

The Bureau devoted one meeting exclusively to review its functions vis-à-vis the mandate of the Bureau.

New Initiatives

While reviewing its mandate, the Bureau felt that there was a need to maintain a database on performance of all officers. Such a database could include personal particulars, trainings and education, promotions, postings, vigilance profile etc. of all senior officers from mandated institutions who were likely to come within the ambit of selection for board level positions in the coming years. The project named “SAMEKAN” is presently under development with Global IT Centre of State Bank of India and is expected to go live in the second half of 2021. Once live, the Bureau as well as all other participating institutions shall be able to get a consolidated view of their senior officers’ profile and can generate benchmark reports on various Human Resource metrics like gender ratios, expertise in specific areas like credit, IT etc., average duration of postings, average age at a particular scale for their institution and of the PSB universe.

“SAMEKAN” is designed as a cloud-based, web-enabled Human Resources Information System that harnesses the latest security and IT functionalities. As the IT infrastructure requires upgradation, the work has been awarded to M/s KWebMaker, which is going on as per schedule.

A new website of the Bureau developed by M/s KWeb Maker went live during the year. The state-of-the-art secured, mobile ready, responsive website has many new features and databases that provide seamless user interface.

As the Bureau issues multiple tenders in a year, the services of M/s MSTC was engaged in order to enable e-tendering using highly secure Digital Signatures, time stamping and logging of all tender related activities. Since its acquisition, all quotes / tenders, irrespective of the amount have been handled only through the e-Tendering Portal. All the key staff members have been issued digital signatures.

Skill Enhancement and Empowerment

In the area of skill development and empowerment of Boards, a need was felt to introduce a programme for Directors of public sector banks / FIs with a view to support them with expert inputs and skill enhancement throughout their tenure. After consulta-

tions with various PSBs and the IBA and after going through the processes, M/s Egon Zehnder International Pvt. Ltd. in collaboration with Harvard¹ Business Publications has been selected to curate the program. The programme is expected to be launched in 2021-22.

The Leadership Development Program, aimed at skill and personality development of senior officers of PSBs, continued with participants from all the PSBs and EXIM Bank. The training for the officers included in the second batch was completely online which included inter alia live projects and events on IIM Bangalore's virtual platform.

Administration

On the administrative front, the Bureau started half yearly audit by external auditors, as a means of assurance and control. The audit covers all the receipt and payments of the Bureau and its related processes.

In another development, the Appointments Committee of the Cabinet approved the extension of the term of the Chairman and Expert members of the Bureau (for PSBs and FIs) for a period of two years beyond April 11, 2020. The term of Shri G N Bajpai and Shri Mathew Verghese, expert members for Insurance Companies, was also extended by one year and Shri N M Govardhan was appointed as a member. Shri M Rajeshwar Rao, Deputy Governor, RBI and Shri A.R. Rizvi were appointed as the ex-officio members for Public Sector Banks and Financial Institutions in Public Sector. On the accounting and housekeeping, the audit of Receipt and Payment Account for 2020-21 was completed and all claims for the year 2019-20, 2020-21 and projections for 2021-22 have been duly received from SBI, IRDAI, and NABARD representing their respective sectors.

.....

¹ Through Harvard Business Publishing (Wholly owned subsidiary of Harvard Business School and their corporate learning arm).

IV. RECOMMENDATIONS FOR APPOINTMENTS

In the year 2020-21, the Bureau processed the recommendations for 38 vacancies in various mandated institutions. The details of institution wise and post wise recommendations is given in Table 1 below. Broadly, the Bureau was tasked with making recommendations for a higher number of positions in the year 2020-21 as compared to the previous year with a larger number of candidates. The ratio of candidates per vacancy is around 4.6 indicating a healthy pool for candidates in line with GoI zone of consideration guidelines of 5 per vacancy which is consistent with industry best practices.

Table 1: Recommendations for appointments made in 2020-21

Designation	FIs	PSBs	PSICs	Total
Chairman	-	1	-	1
CMD	1	-	2	3
DMD	1	-	-	1
MD	-	3	1	4
MD & CEO	1	4	-	5
EDs	-	15	-	15
GM & Director	-	-	9	9
Grand Total	3	23	12	38

Executive Directors in Nationalised Banks

The Bureau has been making recommendations for all the anticipated and clear vacancies since its inception and there is no backlog. The ratio of number of candidates per vacancy was lower at 1.87 in 2020-21 as compared to the average ratio of 2.56 in previous years. This was primarily due to larger number of vacancies of ED in 2020-21 while the number of eligible candidates was lower.

Table 2: Recommendations for Executive Director in Nationalised Banks

Period	Vacancy	Applicants	Candidates Shortlisted	Candidates recommended
2016-17	18	45	45	18
2017-18	15	39	39	15
2018-19	17	44	44	17
2019-20	4*	4	4	4
2020-21	15	28	28	15

* Filled through lateral movement from other PSBs

Managing Director in SBI

For the position of SBI, the Bureau invites applications from the eligible officers of PSBs and SBI. On an average around 8.5 candidates applied for each position of MD in SBI. The practice of getting behavioural assessment done for the candidates of this post was introduced in 2020-21.

Table 3: Recommendations for Managing Director in SBI

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Candidates recommended
2016-17	1	3	3	1
2017-18	1	10	10	1
2018-19	1	11	11	1
2019-20	1	17	17	1
2020-21	3	19	19	3

MD & CEO in Nationalised Banks

The position of MD & CEO in Nationalized banks is filled up through two different processes. While for the four larger banks, applications are invited from the eligible internal candidates as well as from the open market, for the other smaller PSBs the selection is confined only to the eligible internal candidates. As in the other cases, the behavioral assessment is done for all eligible candidates. However, background verification is done for candidates from private sector.

Table 4: Recommendations for MD & CEO in Nationalised Banks

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Behavioural Assessment	Background verification*	Candidates recommended
2016-17	3	10	10	NA	NA	3
2017-18	5	15	15	NA	NA	5
2018-19	12	30	30	NA	NA	12
2019-20	4	62	25	25	9	4
2020-21	4	92	31	31	9	4

* applicable only for candidates from private sector

Chairman in SBI

For the position of Chairman of SBI, only the four MDs of that bank, who would be in service on the date of vacancy, are eligible.

The number of candidates, therefore, cannot exceed four.

Table 5: Recommendations for Chairman in SBI

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Candidates recommended
2017-18	1	4	4	1
2018-19	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-
2020-21	1	4	4	1

NECs in Nationalised Banks: The Bureau has been recommending persons of relevant experience and expertise for the position of Non -Executive Chairman of PSBs. The Bureau has been actively pursuing the matter of appointment of NECs for the current vacancies in PSBs.

Chairman / MD in FIs

The position of Chairman and MDs of FIs are filled up through open advertisement. On an average, 14 candidates appeared for each of these positions.

Table 6: Recommendations for Chairman / MD in FIs

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Behavioural Assessment	Background verification	Candidates recommended
2019-20	2	37	24	24	1	2
2020-21	2	51	33	33	33	2

DMD in FIs

The position of DMDs of FIs are also filled up through open advertisement. On an average, seven candidates appeared for each of these positions.

Table 7: Recommendations for DMD in FIs

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Behavioural Assessment	Background verification	Candidates recommended
2019-20	7	116	40	25	0	2
2020-21	1	23	16	16	4*	1

* background verification is done only for candidates from private sector

Chairman of LIC of India and other positions in Insurance companies

As per extant guidelines, the position of Chairman of LIC of India is filled up from amongst the Managing Directors of LIC subject to fulfillment of the eligibility conditions. Similar guidelines for CMD of other Insurance Companies prescribe that such positions shall be filled up from amongst the eligible Zonal Managers / ZM & Directors etc. The practice of getting behavioral assessment for all candidates appearing for PSIC positions was started in 2020-21.

Table 8: Recommendations for Chairman of LIC of India

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Candidates recommended
2018-19	1	5	5	1
2019-20	-	-	-	-
2020-21	-	-	-	-

Table 9: Recommendations for Chairman and Managing Directors in PSICs

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Behavioural Assessment	Candidates recommended
2019-20	2	7	7	0	2
2020-21	2	10	10	10	2

Table 10: Recommendations for Managing Directors in LIC

Period	Vacancy	Applicants	Shortlisted	Behavioural Assessment	Candidates recommended
2018-19	2	9	9	0	2
2019-20	2	7	7	0	2
2020-21	1	5	5	5	1

V. NEW INITIATIVES

The Bureau has been regularly reviewing its functioning vis-à-vis its mandate with a view to taking steps to advance its efficacy. In this direction, the Bureau made several far-reaching recommendations, chief among which are developing a Directors Development Program and developing a database on Officers of mandated institutions. The progress in implementation of these decisions is reported below.

Directors Development Program

The mandate of the Bureau *inter alia* is to advise the Central Government on evolving suitable training and development programs for banks. In accordance with this mandate, the Bureau deliberated on the utility of a program to support the boards of mandated institutions. It was felt that board members would benefit from a high-quality program to enhance their skills.



In this direction, a discussion paper was placed before the Bureau in its 34th meeting held on August 28, 2020, and thereafter a proposal was submitted in the 37th meeting held on October 5, 2020. The Bureau recommended that while there is a clear case for introduction of such a program, its design should adopt a practitioner's approach. The Bureau created an outline of the program detailing the pedagogy, content etc.

The recommendation for introduction of the program and its broad design contours were placed before the PSBs (through the forum of IBA) and FIs. The proposal was approved by the Managing Committee of the IBA on November 20, 2020, and thereafter a Steering Committee was set up for designing, implementing and initial monitoring of the program.

After e-tendering / competitive bidding, bids of six parties were found technically eligible of which three qualified for commercial bid comparisons. The Steering Committee met on four occasions to complete the entire process and found the program design and

offering by M/s Egon Zehnder International Pvt. Ltd. (partnering with Harvard Business Publications Ltd) as the most suitable.

The program is intended to be offered to all the directors of PSBs and FIs including the nominee directors. The program has three modules viz induction, orientation and refresher. Each of these modules would be delivered in three modes viz. self-paced online mode delivered through Harvard Business Publishing Portal (15-20 hours of content), seminar through online mode (equivalent of 4 days) and in-person interactive mode (3 days). The courseware shall comprise articles, podcasts, case studies, simulation and application activities, role plays, fire side chats and industry interactions. The governance for the program shall be based on the real-time progress tracking of online mode deliveries, surveys, quizzes and reviews.

Who is this Program for:

Directors of PSU Banks and financial institutions (Whole time Directors, Nominee Directors – Government / Regulator, Independent Directors / Non-Official Directors or any other Director on the Board)

Launch:

Scheduled to be launched in the second half of 2021

Key objectives:

- Create an appreciation of principles of corporate governance and their application to building an effective organization.
- Create an appreciation of role of Director in governance, entrepreneurship, and management.
- Generate understanding of the leadership and organizational issues involved in stakeholder management and performance delivery.
- Create a realisation of competencies to maximize the effectiveness of their dealings with the rest of the board as well as with the organization as a whole.
- Gain Knowledge on the latest developments in financial markets, Regulation and Statutes, consumer behaviours, Information Technology and cyber security, Fintech etc.
- Develop key attributes necessary for an effective director

The Director's Development Program seeks to equip directors to answer the following key readiness questions about themselves

Do they ...	Do they ...	Can they ...	What if ...
Know what they need to know about the industry, bank, regulation, legal environment	Have experience that fits the business and its future needs?	Continuously upgrade their capabilities to be effective?	What should be their approach under pressure and in crises?
Emerging business, consumer, technology trends that will impact the business	Bring leadership capabilities that fit current and future role demands?	Make sense of a complex and changing business?	How should they deal with strategic and operational dilemmas?
	Understand and appreciate the demands of the role?	Connect and inspire all stakeholders, inside and outside?	What would be critical in ensuring at times of differing views and perspectives?
	Represent and fit the values of the bank and its stakeholders?	Stay firm in times of troubles and despite opposition?	
Knowledge	Skills	Practical Application	Challenges & Dilemmas

Some of the key features of the program design are given below.

Overall Program Design* - A Practitioners approach to director development



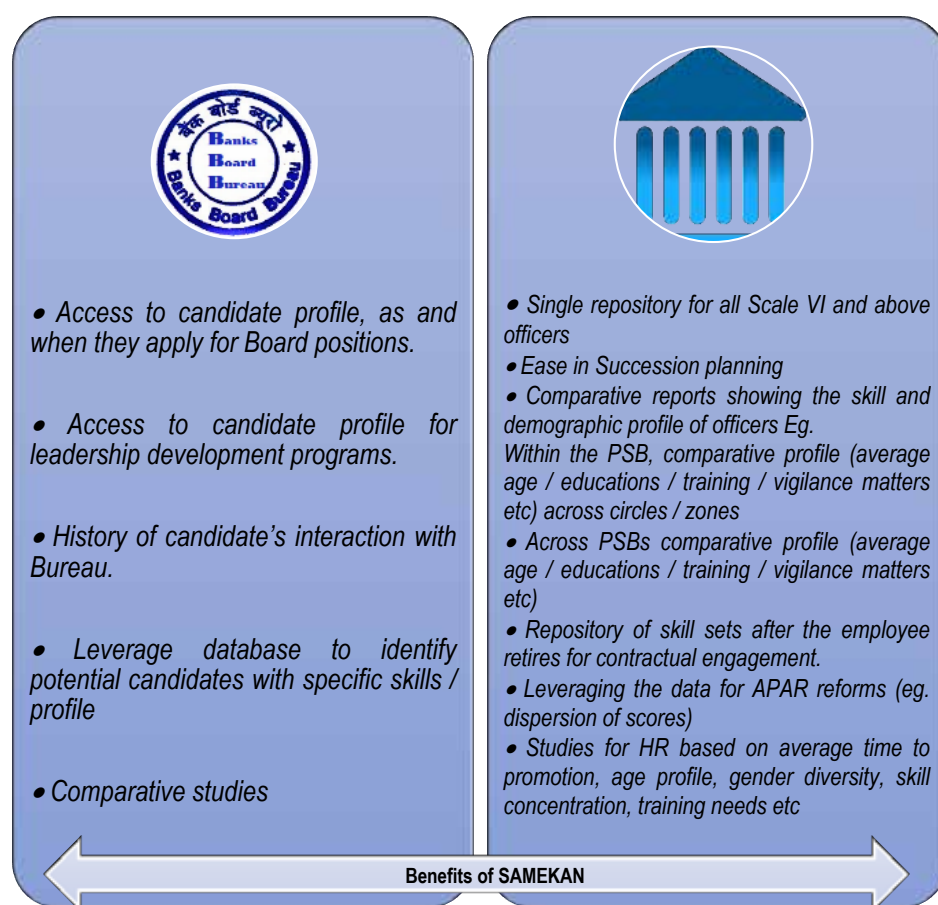
Induction Module for new Directors; Refresher Module for seasoned Directors

**Indicative program design*

The program is in advance stages of design and is expected to be launched shortly.

SAMEKAN (समेकन)

One of the mandates of the Bureau is to maintain a database on the performance of officers of the PSBs. The approach to building this database was discussed in a Bureau meeting held in January 2021. It was felt that the database design should not only inform the Bureau on performance / credentials of officers but should enable the PSBs to leverage it for their own HR analytics and eventually incorporate some of its key features into their own systems. A System Requirement Study was done for a web application that was titled SAMEKAN - System to Assimilate data on Management and Employees service and Knowledge and its ANalysis.

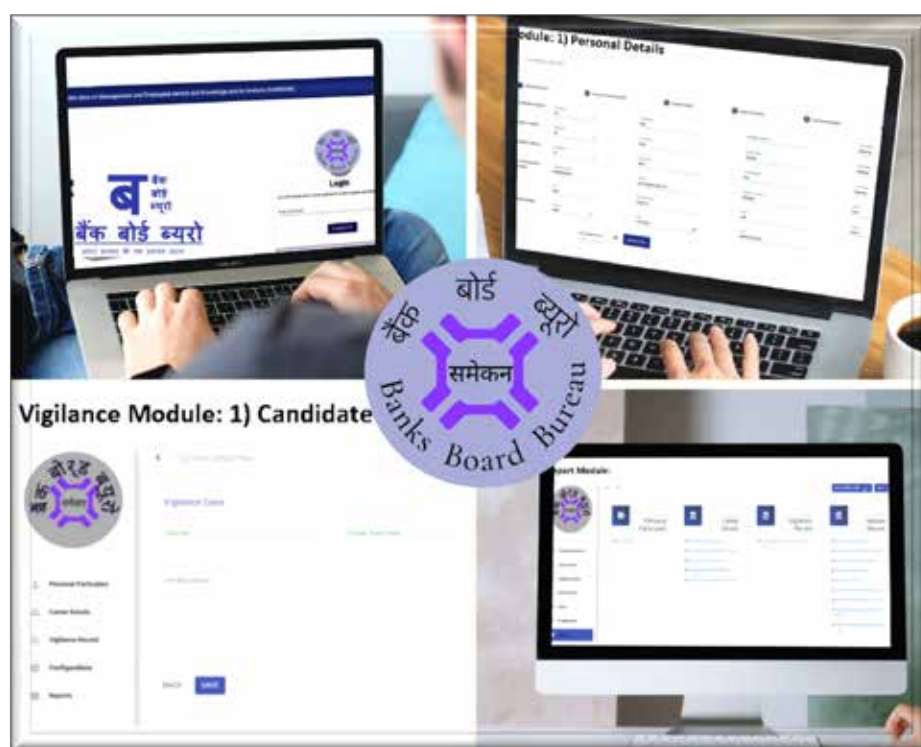


After approaching various PSBs who have in-house software development and delivery capabilities, it was decided that the design and development of the system be done by SBI, who have consented to do the development pro bono. The work has been since been assigned to SBI Global IT Centre (Gitc) at Belapur.

The IT infrastructure setup and management has been outsourced

to M/s KWebMaker. The entire web application, web services and database would be hosted on the cloud and is being designed to meet the security standards of SBI.

At a functional level, SAMEKAN has five major modules that will capture details like personal particulars, training, education, posting and transfers, promotions, vigilance profile, assessments, standard reports, benchmarks etc. The web application would use state-of-the-art encryption and authentication mechanism to ensure security of data. The database is expected to provide a comprehensive profile of all PSB senior officers at a single location and provide PSB level HR benchmarks.

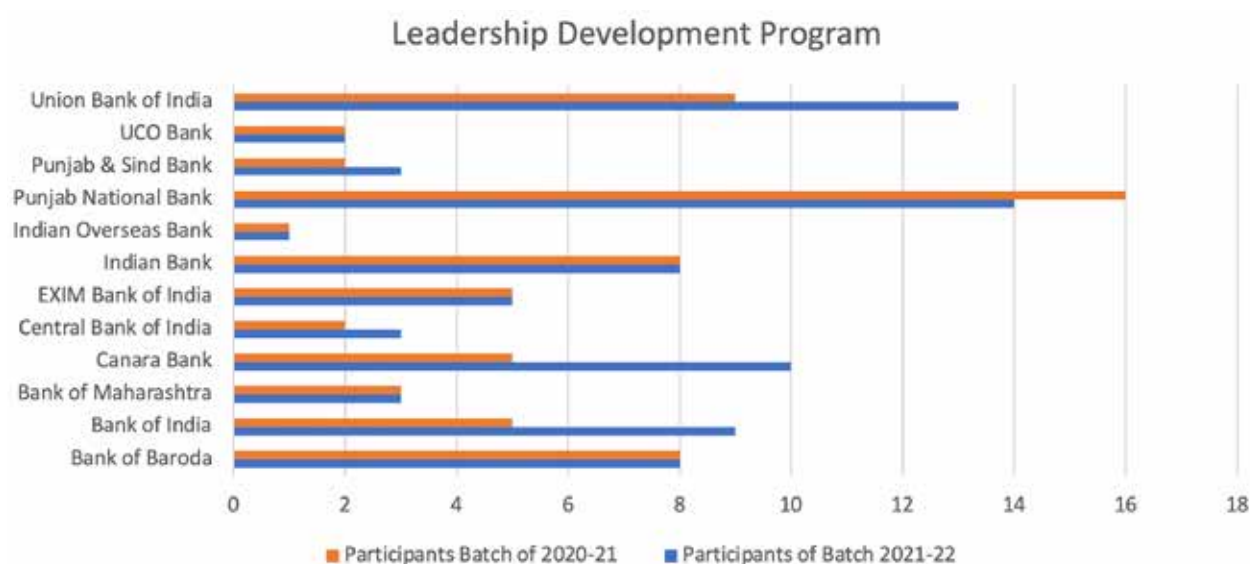


While it will also assist the Bureau in assessment of personages for the Board level vacancies, it will also function as a one-stop window for data included in the system for all administrative and HR related functions. The project is on schedule and is expected to go live in second half of 2021-22.



Leadership Development Program

The First batch of the LDP comprising 78 DGMs and GMs of PSBs concluded on July 17, 2020, having completed all its modules that started from July 19, 2019.



Participant feedback collected by IIM Bangalore after each intervention indicates high level of satisfaction. In addition to the participant survey, 359 officers of various PSBs were surveyed using a structured questionnaire. These officers were identified specifically based on their professional relation with the Trainee Officer viz subordinate, peers and superiors. Majority respondents, irrespective of their professional relation, observed a high degree of improvement in participants. The impact assessment of the “Live Projects” by the MD & CEOs was to the extent of Rs. 4,265 crores. The second batch comprised 66 participants from 12 banks including EXIM Bank, commenced on September 11, 2020. Due to COVID related restrictions, all programme modules were delivered online. As per estimates made by the MD & CEOs of the respective PSBs / EXIM Bank the live projects have resulted in savings of around Rs. 4,122 crore in aggregate.

Since August 16, 2021, the training of the third batch from PSBs and EXIM Bank of 79 participants is currently underway.

VI. DATABASES IT SYSTEMS AND ADMINISTRATIVE WORKS

The Bureau maintains an Office at Mumbai with a lean staff and high usage of IT for optimizing its operations. In view of the pandemic situations, these facilities were further augmented to ensure smooth functioning without compromising on processes and cyber security. On the analytics front, the Bureau continued with the practice of quarterly analysis of financial position of the PSBs. Some new facilities and systems implemented during the year are given ahead.

Video Conferencing Facility

The pandemic situation necessitated acquiring effective VC facilities that allowed the Bureau to conduct its interviews as per the laid down procedures. User licenses for CISCO WebEx were acquired after extensive discussions and trials. The Bureau also prepared and implemented protocols and other documentation to support the online mode for meetings and interactions. The Secretariat also acquired capabilities to e-sign the documents.

Database on Composition of the Boards

The Bureau is mandated to maintain the database on Composition of Boards of the mandated institutions. Hitherto, such a database was maintained on Excel, which did not lend itself to easy anal-

Name	Tenure From	Tenure upto / Vacancy Since	Status
AGRICULTURE INSURANCE CORPORATION OF INDIA			Incumbent
BANK OF INDIA			Incumbent
BANK OF MADRAS			Incumbent
CHENNAI BANK			Incumbent
CENTRAL BANK OF INDIA		01/09/2021	Vacant
COOP BANK			Incumbent
CORPORATE INSURANCE CORPORATION OF INDIA			Incumbent
INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED			Incumbent
INDIA POST PAYMENTS BANK			Incumbent
INDIAN OVERSEAS BANK			Incumbent
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA			Incumbent
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT			Incumbent
NATIONAL HOUSING BANK			Incumbent
NATIONAL INSURANCE CORPORATION LIMITED			Incumbent

ysis and disclosure. In order to streamline the entire process, an online database on Composition of the Board was created with a web application fully integrated with a Content Management System (CMS). This

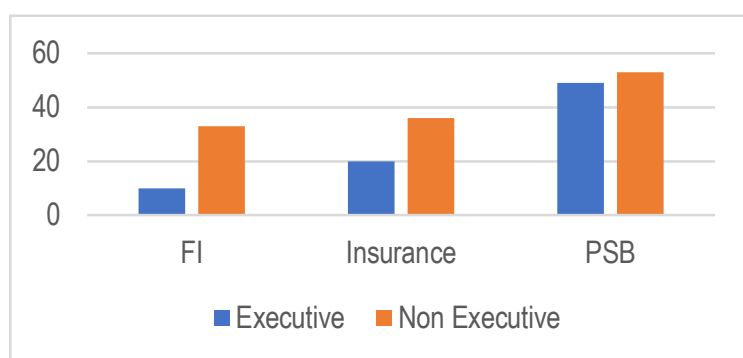
web application is secured with round the clock site security, monitoring and backup. The CMS enables the Bureau to maintain the database through a secure interface.

The database is integrated with the website of the Bureau and allows the user to generate reports showing the incumbent and the retired board members, their tenures etc apart from the vacant positions.

The user can also generate a special report showing the institution-wise list of personages, whose tenure is getting over in the next six months. The user also has an option to generate various other reports using filters. The Secretariat regularly updates the data to ensure its currency.

Institutions under Mandate of the Bureau

The Bureau has been tasked with recommending personages for board level positions in Nationalised Banks, State Bank of India, India Post Payment Bank, NABARD, SIDBI, EXIM Bank, NHB, IFCI Ltd, IIFCL and Public Sector Insurance Companies.



Category of Institutions	Number
PSBs (Including IPPB)	13
PSICs	7
FIs	6

In terms of composition of the Boards of the mandated institutions, presently the boards of PSBs usually have equal presence of Non-Executive and Executive members. On the other hand, on the whole, the boards of Insurance companies FI in public sector, currently have higher number of non-executive members.

New Website of the Bureau

The Bureau's new website went live in December 2020. The cloud-based website design, hosting and security are based on the state-of-the-art technologies and is fully integrated with a WordPress based Content Management System that allows the Secretariat to quickly update the content without depending on any external vendor. The website is also integrated with SurveyMonkey for accepting online applications, with Twitter for display of feeds from the Bureau's verified handle (@BanksBoardBuro), with a MySQL database on Composition of Boards, with a firewall, with Google analytics etc.

Twitter Handle

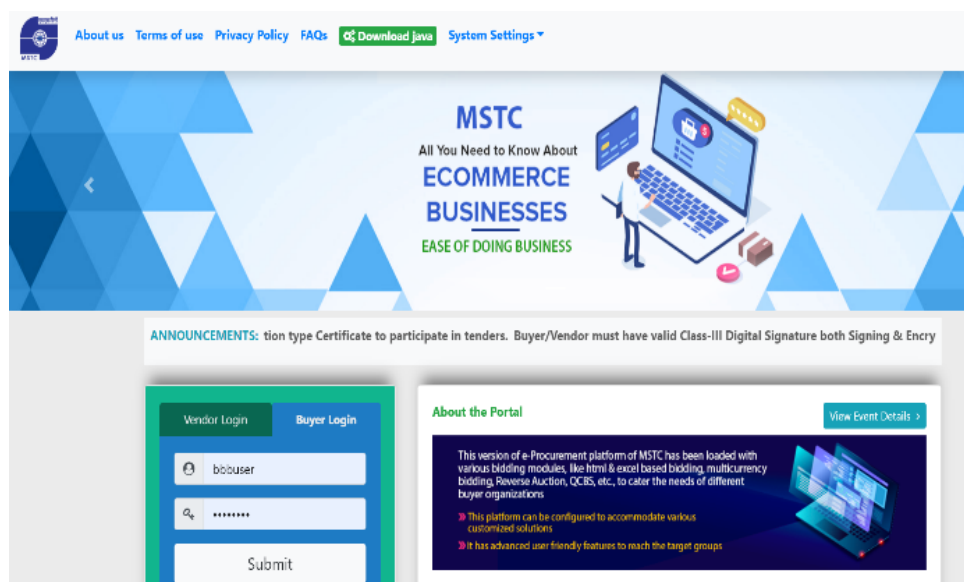
The verified Twitter handle @BanksBoardBuro for Banks Board Bureau was also made live with the new website. The handle is integrated with the website, so that user does not miss on any notices and information published on either of the sources. Since its launch, all key notifications, tender notices, applications, recommendations etc are published on the twitter handle and website simultaneously.



E-Tendering Portal

The Bureau has been issuing tenders and calling for quotations for procurement of various services. In order to fully comply with the requirements of the Central Vigilance Commission, the Bureau has now on-boarded itself onto the E-Procurement portal of the M/s MSTC Ltd.

The portal provides for the fully secure online e-tendering system. All tendering process, irrespective of the value, for procurements by the Bureau are being done on this portal since 12-January-2021.



Officers of the Bureau have acquired class 3 digital certificates from E-mudhra for the purpose.

Right to Information

The Bureau received 12 requests for information and 4 appeals under the RTI Act during 2020-2021. One matter went into second appeal to Chief Information Commission and was dismissed. Two training programmes on the RTI Act were conducted by the RBI, Zonal Training Centre, Chennai, and Kolkata during the year. As the Bureau staff is from RBI, these programs were available to them as well.

The Bureau had hitherto been receiving RTI applications in physical form only as it was not listed on the RTI Public Portal. The Bureau was onboarded on the RTI Online Portal for Public Authorities and went live on 5-March-2021 and all the processes related to receipt, response, appeal are now being done online on the portal. Members of public can now file online RTI applications through www.rtionline.gov.in. The Bureau has been making suo motu disclosures on its website. The College of Agricultural Banking, Pune is the Transparency Auditor. Audit report of the first audit have been submitted to the Chief Information Commissioner.

The Bureau has two committees viz. Consultancy Committee on suo-motu disclosures and another one to identify frequently sought information under RTI. The recommendations of these committees have been duly incorporated into the disclosures available on the Bureau's website.

VIII. RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

Receipts: The Receipts of the Bureau are inflows from various Public Sector Banks, Insurance companies and Financial Institutions that are currently within the remit of the Bureau. The expenses (both incurred and projected) are divided among the institution categories i.e., Public Sector Banks, Insurance companies and Financial Institutions, in proportion of the vacancies that were serviced by the Bureau. As per the extant directions, the nodal institution for PSBs is State Bank of India, for Insurance Companies is IRDAI and for Financial Institutions is NABARD.

The dues for 2019-20 and 2020-21 have been fully received from State Bank of India, NABARD and LIC (nodal institution as per IRDAI). As per the extant guidelines, the Bureau is required to project its expenses and distribute it among the institutions in proportion of the vacancies as on April 1 of the year. Accordingly, the Bureau has made projections of its expenses for 2021-22 and raised demand on SBI, IRDAI and NABARD. The full payments from all these institutions have been received.

The receipts and payments of the Bureau are routed through accounts maintained at Reserve Bank of India.

Payments: The major payments are related to lease rentals towards hiring of premises at Mumbai and personnel costs that are reimbursed to Reserve Bank of India. These constitute the recurring expenses for the Bureau. The External HR agency charges are incurred for assessment and background verification of candidates. There are no fixed assets as majority of the fixtures, furniture and computer hardware etc. are provided by RBI. Minor items of hardware are considered as revenue expense.

In terms of efficiency, the Talent Acquisition Cost (Total Expenses

divided by number of vacancies) works out to Rs. 2.44 lakh only in 2020-21 as against Rs. 17.4 lakh per vacancy in 2019-20. This reduction is primarily due to the higher number of candidates being assessed with no significant increase in fixed expenses and only a proportionate increase in variable expenses.

Receipts and Payment Statement for the year ended 31st March 2021

(Rupees)

PAYMENTS				RECEIPTS			
Particulars	Amount	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020	Particulars	Amount	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Advertisement Charges		73,08,882	32,83,510	Pending receipts for 2020-21	2,06,34,952		
Personnel Cost		1,53,73,330	1,46,49,473	Less Received from NABARD	1,56,38,108		1,06,41,265
Rental Charges		63,90,000	63,90,000	Less received from LIC	49,96,844		2,06,34,952
Travelling Expenses				Reimbursement Received for 2021-22			
Fare	1,90,345			State Bank of India	1,43,44,342		
Hotel	32,878			LIC	1,48,07,557		
Car Hire	20,686	2,43,909	15,55,485	NABARD	32,39,100	3,23,90,999	
HR Agencies Charges		82,75,340	18,46,700	Excess of Expenditure (payment) over Reimbursement (Receipts) for the year and to be received in Subsequent Year		1,01,49,026	
Sitting Charges							
PSIC Members	9,50,000						
PSB Expert Member	23,50,000	33,00,000	19,70,000				
Purchase of Assets		-	4,01,760				
Software Charges		9,28,142	97,451				
Postage		5,05,597	2,77,236				
Miscellaneous Expenses		2,14,825	1,44,391				
TOTAL		4,25,40,025	3,12,76,217			4,25,40,025	3,12,76,217

SCA AND ASSOCIATES
Chartered Accountants

B-104, Kanakia Zillion, BKC Annexe
LBS/CST Road Junction
Near Kurla Bus Depot, Kurla West
Mumbai - 400070
Ph-02262450777
Email-mail@scaassociates.com.
Website-www.scaandassociates.com

Independent Auditors' Report

The Secretary
Banks Board Bureau

Opinion

1. We have audited the accompanying statement of Receipts and Payments (the statement) of M/s Banks Board Bureau (BBB) for the year ended March 31, 2021. The statement has been prepared by management of Banks Board Bureau to give the True and Fair view of the payments made and corresponding receipts/to be received of the Banks Board Bureau.
2. In our opinion, the statement presents a true and fair view of the Receipts and Payments of Bank Board Bureau for the year ended March 31, 2021.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the statement section of our report. We are independent of the Banks Board Bureau in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with Code of Ethics. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibility of Management for the Statement

4. Management of Bank Board Bureau is responsible for the preparation and fair presentation of this statement to give the True and Fair view of the payments made and corresponding receipts of the Banks Board Bureau. This responsibility also includes maintenance of adequate records and for the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of the statement that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Statement

5. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the statement as a whole is free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these statement.
6. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also Identify and assess the risks of material misstatement of the statement, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

SCA AND ASSOCIATES

Chartered Accountants

B-104, Kanakia Zillion, BKC Annexe

LBS/CST Road Junction

Near Kurla Bus Depot, Kurla West

Mumbai-400070

Ph-02262450777

Email-mail@scaassociates.com.

Website-www.scaandassociates.com

7. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

Restriction on distribution or use

8. The accompanying statement have been prepared solely for information and use of Bank Board Bureau only and accordingly may not be suitable for any other purpose. This report is issued solely for the aforementioned purpose and accordingly, should not be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other party without our written consent. Further, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For SCA AND ASSOCIATES

Chartered Accountants

Firm Registration No.:101174W

Shivratan Agarwal

Partner

Membership Number: 104180

UDIN: 21104180AAAAEG4933

Mumbai, May 17, 2021

बैंक्स बोर्ड ब्यूरो

BANKS BOARD BUREAU

4th floor, Reserve Bank of India
Byculla Office Building,
Mumbai Central,
Mumbai - 400 008

चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक,
डॉ आनंद राव नायर मार्ग, मुंबई सेंट्रल,
मुंबई - ४०० ००८